परम हंसदा और अन्य
बनाम
बिहार राज्य (वर्तमान झारखंड)
नवंबर 22, 2006

[एस. बी. सिन्हा और मार्कडेय काटजू, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860; धारा 304 और 342:

हमला और हत्या-आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से चोरी करने के लिए पकड़े गए वादी के पिता-आरोपी और ग्रामीणों द्वारा हमला- घायल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया- विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 304 और 342 के तहत अपराध करने का दोषी पाया और उन्हें तदनुसार सजा सुनाई, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-अपील पर, अभिनिर्धारित : मृतक पर न केवल अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बल्कि ग्रामीणों द्वारा भी हमला किया गया और पीटा गया-घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था-हालांकि कुछ गवाहों ने बयान दिया कि आरोपी ने मृतक को पीटा था, लेकिन उनके सबूत विश्वसनीय नहीं थे-क्योंकि आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार था-दोषसिद्धि और अभियुक्त की सजा को दरकिनार कर दिया गया-निर्देश जारी किए गए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी के पिता को आरोपी व्यक्तियों ने कथित रूप से उनके घर में चोरी करने के आरोप में पकड़ा था और उनके और ग्रामीणों द्वारा बेरहमी से हमला किया गया था। मृतक के बेटे ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पीड़ित ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण अदालत ने दोनों आरोपी व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 304 और 342 के तहत अपराध करने का दोषी पाया और उन्हें तदनुसार सजा सुनाई। विचारण अदालत के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसलिए, वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को स्वीकृत करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1. मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि मृतक ने आरोपी व्यक्तियों के घर में चोरी करने की कोशिश की थी, जिसके दौरान उसे आरोपी ने पकड़ लिया था। उन्होंने गाँव के मुखिया से संपर्क किया और एक पंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

1.2. घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ गवाहों ने विचारण अदालत के समक्ष गवाही दी है कि यह आरोपी था जिसने मृतक को पीटा था; प्राथमिकी में दिए गए संस्करण को देखते हुए इस बिंदु पर साक्ष्य को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

1.3. प्राथमिकी के हिस्से के अवलोकन से ऐसा लगता है कि मृतक पर अन्य ग्रामीणों ने लाठी और डंडे से हमला किया था। इस प्रकार इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक को अन्य ग्रामीणों द्वारा पीटा गया था और आरोपी द्वारा नहीं। अतः वे संदेह के लाभ के हकदार हैं।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 115/2006।

झारखंड उच्च न्यायालय रांची के निर्णय और आदेश दिनांकित 05.05.2003
आपराधिक अपील सं. 38/91 (पी) से।

अपीलार्थियों के लिए गौरव अग्रवाल।

प्रतिवादी के लिए बी. बी. सिंह (कृष्णानंद पांडे के लिए)।

न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया गया:

मार्कडेय काटजू, न्यायाधीश यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 5.5.2003 आपराधिक अपील संख्या 38/1991 (पी) के खिलाफ दायर की गई है।

पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अध्ययन किया।

अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि वादी के पिता झरिया किस्कु सोमवार को सिमलॉग हटिया गए थे और जब वह रात में जब वह नहीं लौटे, तो अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे, प्रामे हंसदा (अपीलकर्ता संख्या 1) ने वादी को सूचित किया कि उनके पिता झरिया किस्कु को सोमवार की रात को अपने घर में एक बाती की चोरी करते हुए पकड़ा गया था और उसके बाद उन्हें रस्सी से बांध दिया गया था। इसके बाद वादी मुकदमा और अन्य लोग बाराघाघड़ी गए और उन्होंने प्रधान के घर में झराई किस्कु को बंधा हुआ पाया। उनके आने पर एक पंचायत बुलाई गई। यह कहा गया था कि एक भाटी की चोरी करने के बाद, झरिया किस्कु भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया और उस पर हमला किया गया और उसे रस्सी से बांध दिया गया। रु.100/- की राशि का जुर्माना भी पंचायत द्वारा लगाया गया था। झरिया किस्कु से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि उनके खिलाफ चोरी का झूठा आरोप लगाकर अपीलकर्ताओं ने लाठी और डंडा द्वारा उन पर बेरहमी से हमला किया गया था, रस्सी से बंधा हुआ था। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच की और अपीलार्थियों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए जहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 304 के तहत आरोपित किए गए, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।

साक्ष्य पर विचार करने और विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, विचारण न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांकित 08.11.1990 के अनुसार आरोपी परमे हंसदा और चुरका हंसदा को दोषी पाया और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 304 और 342 के तहत दोषी ठहराया।

उपरोक्त फैसले के खिलाफ, उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी जिसे विवादित फैसले दिनांक 5.5.2003 पर खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान अपील प्रस्तुत किया गया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक पर निम्नलिखित चोटों का पता चलता है:

- (i) एक फटा हुआ घाव दाहिने अग्र-भुजा के अल्ना पक्ष पर 2 "x 1/2" x हड्डी की गहराई तक।
- (ii) एक फटा हुआ घाव बाएं निचले पैर में घुटने के जोड़ से 5 "नीचे 1" x 1 "x हड्डी की गहराई तक।
- (iii) माथे के बाईं ओर 1 "x 1" मापने वाला एक खरोंच।
- (iv) सिर के दाहिने हिस्से की पार्श्विका हड्डी टूट गई और दबी हुई।
- (v) दोनों क्षेत्रों पर गहरा निशान।

मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि मृतक ने अपीलार्थियों के घर में चोरी करने की कोशिश की थी, जिसके दौरान उसे अपीलार्थियों ने पकड़ लिया था। अपीलकर्ताओं ने गाँव के मुखिया से संपर्क किया और एक पंचायत बुलाई गई जिसने उस पर सौ रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके बाद जो हुआ उसका उल्लेख प्राथमिकी में किया गया है जिसमें कहा गया है:

“....इसके बाद, हमने अपने पिता से पूछा, जिन्होंने कहा कि पिछली रात परमे हंसदा और चुरका हंसदा ने उन पर लाठी और डंडे से हमला किया था और चोर-चोर चिल्लाया था। यह सुनकर, कई लोग वहाँ आए और यह सोचकर कि मैं चोर हूँ, मुझे पर लाठी और डंडे से हमला किया और मुझे घायल कर दिया। इसके बाद, उन्होंने मुझे प्रधान जेठा हेम्ब्रम को सौंपा, जिन्होंने मुझे रात भर और अगले दिन 1:00 बजे उसके घर पर रस्सी से बंधा जुर्माना वसूलने की दृष्टि से रखा हुआ था। मंगलवार को 1:00 बजे, हम उसे जुर्माना भरने

के बाद ला रहे थे, जब उसकी दधी गाँव में मृत्यु हो गई। यह मेरा बयान है, जिसे दर्ज किया गया है और हस्ताक्षर किए गए हैं।“

ऊपर वर्णित की गई प्राथमिकी के हिस्से के अवलोकन से ऐसा लगता है कि मृतक पर अन्य ग्रामीणों ने लाठी और डंडे से हमला किया था। इस प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक को अन्य ग्रामीणों द्वारा पीटा गया था और अपीलकर्ताओं द्वारा नहीं। इसलिए, हमारी राय में अपीलार्थी संदेह के लाभ के हकदार हैं।

हमने इस मामले में भी सबूतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ गवाहों ने विचारण अदालत के समक्ष गवाही दी है कि यह अपीलकर्ता थे जिन्होंने मृतक को पीटा था, प्राथमिकी (ऊपर उल्लिखित) में दिए गए संस्करण को देखते हुए इस बिंदु पर साक्ष्य को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

अपीलार्थी पहले ही 5 साल के कारावास से गुजर चुके हैं।

ऊपर दिए गए कारणों के लिए, अपील स्वीकृत की जाती है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि वे किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

अपील स्वीकृत।

Ashish Kumar